I.G.N.O.U. *Based*

NEERAJ®

E.P.S.-9

तुलनात्मक सरकार और राजनीति

(Comparative Government and Politics)

By: *Sunil Kumar Gupta*, M.A. (Pol. Science)

Question Bank** Cum **Chapterwise Reference Book
Including **Many Solved Question Papers**

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)
(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

Sales Office:
1507, Ist Floor, Nai Sarak, Delhi - 6
Ph.: 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501
E-mail: info@neerajignoubooks.com
Website: www.neerajignoubooks.com

MRP ₹ **200/-**

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

Sales Office : **1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110 006**
E-mail: **info@neerajignoubooks.com**
Website: **www.neerajignoubooks.com**

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only	*Typesetting by:* ***Competent Computers***	*Printed at:* ***Novelty Printer***

Notes:

1. *For the best & upto-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board /University.*
3. *The information and data etc. given in this Book are from the best of the data arranged by the Author, but for the complete and upto-date information and data etc. see the Govt. of India Publications/textbooks recommended by the Board/University.*
4. *Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc. are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book.*
5. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
6. *If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to inform the Publisher, so that the same could be rectified and he would be provided the rectified Book free of cost.*
7. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
8. *Question Paper and their answers given in this Book provide you just the approximate pattern of the actual paper and is prepared based on the memory only. However, the actual Question Paper might somewhat vary in its contents, distribution of marks and their level of difficulty.*
9. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS/NEERAJ IGNOU BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc. is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ IGNOU BOOKS/NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
10. *Subject to Delhi Jurisdiction only.*

© Reserved with the Publishers only.

Spl. Note: *This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*

How to get Books by Post (V.P.P.)?

If you want to Buy NEERAJ IGNOU BOOKS by Post (V.P.P.), then please order your complete requirement at our Website ***www.neerajignoubooks.com****. You may also avail the 'Special Discount Offers' prevailing at that Particular Time (Time of Your Order).*
To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ IGNOU BOOKS You may Visit/Surf our website ***www.neerajignoubooks.com.***
No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges.
We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days).

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110006

Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501

E-mail: **info@neerajignoubooks.com** *Website:* **www.neerajignoubooks.com**

CONTENTS

तुलनात्मक सरकार और राजनीति
(Comparative Government and Politics)

Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—June, 2019 (Soved)	1-4
Question Paper—December, 2018 (Soved)	1-3
Question Paper—June, 2018 (Soved)	1-2
Question Paper—December, 2017 (Soved)	1-2
Question Paper—June, 2017 (Soved)	1-2
Question Paper—December, 2016 (Soved)	1-2
Question Paper—June, 2016 (Soved)	1
Question Paper—December, 2015 (Soved)	1-2
Question Paper—June, 2015 (Soved)	1-2
Question Paper—December, 2014 (Soved)	1-2
Question Paper—June, 2014 (Soved)	1
Question Paper—December, 2013 (Soved)	1-3
Question Paper—June, 2013 (Soved)	1-2
Question Paper—December, 2012 (Soved)	1-2
Question Paper—June, 2012 (Soved)	1-2
Question Paper—June, 2011 (Soved)	1
Question Paper—June, 2010 (Soved)	1

S.No. ***Chapterwise Reference Book*** *Page*

तुलनात्मक विधि और दृष्टिकोण

1. राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता 1
2. तुलनात्मक प्रविधि और तुलना के तरीके 6
3. संस्थागत दृष्टिकोण.. 10

S.No.	*Chapter*	*Page*

4. व्यवस्था दृष्टिकोण **13**

5. राजनैतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण **19**

<u>राष्ट्रीय आन्दोलन तथा उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष</u>

6. राष्ट्रीय आन्दोलनों की विचारधारा, सामाजिक आधार तथा उनके कार्यक्रम **22**

7. उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष के प्रतिमान **25**

8. औपनिवेशिक युग में राज्य-निर्माण की गत्यात्मकता **29**

<u>समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य</u>

9. सामाजिक संरचना एवं स्तरीकरण **33**

10. वर्गीय संरचना **36**

11. शक्ति के सामाजिक आधार **40**

12. विकास संबंधी कार्यनीतियाँ **43**

<u>राजनीतिक प्रणालियों का वर्गीकरण</u>

13. शासन प्रणालियों के वर्गीकरण की पद्धतियाँ **47**

14. लोकतांत्रिक तथा अधिनायकवादी शासन प्रणालियाँ/पद्धतियाँ **51**

15. असैनिक और सैनिक शासन प्रणालियाँ **54**

16. धर्मनिरपेक्षता तथा धर्मविलम्बित/धर्म-आधारित शासन प्रणालियाँ **58**

<u>संस्थाएँ और सरकार के प्रकार</u>

17. शासन के अंग : कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका **62**

S.No.	*Chapter*	*Page*

18. एकात्मक और संघीय प्रणालियाँ : संघीय प्रणालियों के प्रतिमान और प्रवृत्तियाँ **67**

19. गणराज्यवाद **71**

राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के विभिन्न रूप

20. राजनीतिक दलीय व्यवस्थाएँ **75**

21. दबाव समूह **79**

22. चुनाव प्रक्रिया **82**

सामाजिक आंदोलन

23. श्रम संगठन आंदोलन **86**

24. कृषक वर्ग **92**

25. महिला आंदोलन **96**

26. पर्यावरण **101**

27. मानवाधिकार **106**

भूमंडलीकरण तथा विकासशील विश्व

28. भूमंडलीकरण : पृष्ठभूमि और विशेषताएँ **112**

29. विकासशील समाजों पर भूमण्डलीकरण का प्रभाव **116**

30. भूमण्डलीकरण तथा विकासशील देशों की अनुक्रिया **121**

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER
(June – 2019)
(Solved)

तुलनात्मक सरकार और राजनीति

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

*नोट : (i) **भाग-I**-किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिये। (ii) **भाग-II**-किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिये।*
*(iii) **भाग-III**-किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिये।*

भाग–I

निम्नलिखित में से *किन्हीं दो* प्रश्नों के उत्तर दें–

प्रश्न 1. चीन की विकास रणनीतियों पर एक निबंध लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-12, पृष्ठ 44, 'विकास संबंधी चीनी कार्यनीति'

इसे भी देखें–चीन में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1953-1957) का लक्ष्य यह रखा गया कि तेज गति से व्यापक औद्योगिक ढांचे की नींव रखी जाए। पूंजीगत माल के क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी गई (50 प्रतिशत से अधिक का निवेश किया गया।) उपभोक्ता माल की वृद्धि को अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिया गया। कृषि को केवल 6.2 प्रतिशत दिया गया तथा उसे प्राय: किसानों की व्यक्तिगत पहल के लिये छोड़ दिया गया। सोवियत संघ ने चीन को ऋण के रूप में लगभग 3 अरब डॉलर की राशि दी तथा तकनीकी एवं विशेषज्ञता संबंधी अत्यावश्यक सहायता भी प्रदान की।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्ष गंभीर आर्थिक मंदी में और अंतिम दो वर्ष पुनर्योजन की नीति में बीते। फिर 1963-65 के तीन वर्षों में और भी अधिक पुनर्योजन किया गया। इसे द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बीच का संक्रमण काल माना गया।

सन् 1966 में चीन ने अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सफलतापूर्वक पुनर्योजन कर लिया था, गंभीर आर्थिक कठिनाइयों पर काबू पा लिया था और तृतीय पंचवर्षीय योजना को लागू करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक उसी समय माओ जेदुंग ने अपनी 'सांस्कृतिक क्रान्ति' प्रारंभ की। डैंग जिओपिंग के मत से उसमें क्रांति जैसी कोई बात थी ही नहीं। वह एक आंतरिक अव्यवस्था थी जिसने पूरे एक दशक के लिये चीन के आर्थिक विकास को तहस-नहस कर दिया।

1976 में माओ जेदुंग की मृत्यु के तथा माओ की वफादार 'चौकड़ी' के दमन के पश्चात्, सत्ता डैंग जिओपिंग एवं तथाकथित 'पूंजीवादी वर्ग के पथिकों' के हाथों में आ गई। नए नेतृत्व ने बड़े पैमाने पर उस दिशा में आर्थिक सुधार लागू किए जिसे उन्होंने 'चीनी लक्षणों वाला समाजवाद' कहा। व्यवहार में यह कदम विकास के लिये माओ द्वारा लागू की गई उस नीति का निराकरण था, जिसमें माओ ने चीन की अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक स्थितियों में ही समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न किया था। इस नीति ने चीन को नव्य उदारवाद की दिशा में धकेल दिया। यद्यपि आधिकारिक रूप से डैंग ने कहा था कि आर्थिक विकास की नई कार्यनीति का 'बुर्जुआ उदारवाद' से कोई संबंध नहीं था। सरकार ने सामूहिक स्वामित्व वाली कृषि-भूमि को उत्तराधिकार के प्रावधानों सहित, दीर्घकालीन पट्टेदारी के आधार पर, किसानों में बांटकर खेती में **'पारिवारिक दायित्व पद्धति'** को लागू किया। यह चोर दरवाज़े से चीन में निजी स्वामित्व वाली खेती को पुनर्प्रविष्ट कराना ही था। इस नई पद्धति ने किसी सीमा तक ग्रामीण समाज में असमानता को बढ़ावा दिया, किन्तु इससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। चीन में सोवियत संघ की अपेक्षा यंत्रीकरण का स्तर नीचा होते हुए भी, चीन की परिवार आधारित खेती सोवियत संघ की सामूहिक खेती की अपेक्षा उत्पादन की दृष्टि से बेहतर सिद्ध हुई थी। साम्यवादी दल के बारहवें और तेरहवें सम्मेलनों के बीच के पांच वर्षों में आर्थिक सुधारों तथा बाहरी जगत के लिये अपनी अर्थव्यवस्था में छूट देने की शुरुआत दृष्टि से चीन ने बहुत प्रगति की। औद्योगिक पुनर्संरचना सम्पन्न हो गई थी। उत्पादक एवं लाभकारी उद्यमों में निवेश बढ़ा दिया गया था। कृषि, ऊर्जा संसाधनों, परिवहन एवं संचार को विशेष समर्थन दिया गया था। सन 1990 तथा 1999 के बीच सकल राष्ट्रीय उत्पाद की औसत वृद्धि दर 10 से 11 प्रतिशत वार्षिक हो गई। इस दौर में, चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से उदारीकृत एवं निजीकृत हुई थी। यह जिस पद्धति से किया गया था चीनी उसे **'संविदात्मक उत्तरदायित्व पद्धति'** कहना पसंद करते हैं। इसमें भूमि तथा संपत्ति प्राप्तकर्त्ताओं को पट्टेदारी के दीर्घकालीन अधिकार दिए गए थे।

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

प्रश्न 2. नए भूमंडलीकरण को स्वीकार करने के पीछे के कारकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-29, पृष्ठ 116,'भूमण्डलीकरण', पृष्ठ 118, 'विकासशील देशों की परम आवश्यकताएं'

प्रश्न 3. किसान-वर्ग की पहचान की परिभाषा और समस्या पर एक निबंध लिखिए।

उत्तर–कृषक वर्ग की कोई परिभाषा नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्र के अनेक तबकों को जोड़ने या घटाने से प्रस्तुत अस्पष्टता तथा कृषक वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका की आंशिक समझ से उत्पन्न होता है। कृषक का शाब्दिक अर्थ है साधारण औजारों से भूमि पर कार्य करने वाला व्यक्ति। सारी की सारी ग्रामीण जनता जिनमें बड़े जमींदार तथा खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं, कृषक मान लिए गए हैं। इस परिभाषा में वर्गीकरण करने से विभिन्न श्रेणियों में भूखण्डों, प्रौद्योगिकी, रोजगार श्रम का प्रयोग आदि से उत्पन्न विभिन्नताओं की अनदेखी हो जाती है।

कृषक वर्ग की कुछ परिभाषाएं हैं। कृषक संघर्षों के विद्वान एरिक वोल्फ (Exie Wolf) ने उन्हें ऐसे लोग कहा है जिनका अस्तित्व खेती में संलग्नता से जुड़ा है और वे खेती की प्रक्रियाओं के संबंध में स्वायत्त निर्णय लेते है। इस परिभाषा में निर्धन और सीमान्त किसान तथा बंटाईदारों (share croppers) की श्रेणियां सम्मिलित नहीं हैं। दूसरी ओर, एक अन्य विद्वान **थियोडोर शैनिन** (Theodar Shanin) उन्हें वह लोग मानता है, जो छोटे कृषि उत्पादक हैं, जो साधारण औजारों और अपने पारिवारिक श्रम द्वारा मुख्य रूप से अपने उपभोग के लिए और आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के प्रति अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। यह परिभाषा उन धनिकों और पूंजीपतियों को इस श्रेणी में शामिल नहीं करती, जो अधिकतम लाभ के लिए विस्तृत बाजार में प्रवेश करते हैं। इरफान हबीब ने भी एक सरल परिभाषा दी है। वह कृषक उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने आप, अपने पारिवारिक उपकरणों द्वारा कृषि करता है। इन परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए कृषक वर्ग को ''जनसंख्या की वह कोटि माना जा सकता है जिनके पास कुछ भूभाग है, जो कृषि उत्पादन के लिए मुख्यत: पारिवारिक या भाड़े के श्रम पर निर्भर है, जो प्रतियोगी बाजार या सीमित बाजार व्यवस्था में विश्वास रखता है।''

तथापि सभी को कृषक वर्ग नहीं कहा जा सकता। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों व भूमिहन मजदूरों के भी वर्गीकरण हैं। उदाहरण के लिए, किसान, उत्पादन के संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग की आशा करता है और बाजार का जोखिम उठाने को तैयार रहता है। कृषक से किसान में परिवर्तन मात्र मनोवैज्ञानिक ही नहीं वरन् भौतिकवादी भी है, परन्तु भूमि से जुड़ा होने के कारण उसे भी कृषक मान लिया जाता है।

खेतिहर मजदूरों को भी कृषकों की श्रेणी में मान लिया जाता है, क्योंकि भूमि के विकास में उनकी संलग्नता और उसके उत्पाद का उनके लिए महत्त्व उनके लिए भी उतना ही है जितना भूमि के मालिकों व उनके जोतने वालों के लिए। भूमि दोनों के लिए एक तत्त्व है और किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक व तकनीकी परिवर्तन अपनी भूमि पर खुद खेती करने वालों तथा खेतिहर मजदूरों दोनों को प्रभावित करता है।

भूमिहीन मजदूर कृषक वर्ग से मनोवैज्ञानिक व व्यवहार में भिन्न है। वह निश्चित मजदूरी, काम के निश्चित घंटे, उचित शैक्षणिक व स्वास्थ्य सुविधाओं व क्रय शक्ति में वृद्धि को वरीयता देता है।

जनजातियों को भी कृषक वर्ग मान लिया जाता है विशेषत: उनको जो किसी क्षेत्र विशेष में दीर्घकाल से बसे हैं और भूमि पर कार्य करते हैं। भू-संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उन्हें भी समान रूप से प्रभावित करता है।

इसे भी देखें–अध्याय-24, पृष्ठ 92, 'कृषक वर्ग का वर्गीकरण'

प्रश्न 4. महिलाओं के मताधिकार आंदोलनों (Women's Suffrage Movements) का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-25, पृष्ठ 96,'पृष्ठभूमि और इतिहास'

इसे भी देखें–अमेरिका में दास प्रथा के विरुद्ध संघर्ष के दौरान महिलाओं और अश्वेत गुलामों के लिए मताधिकार की मांग की गई। 1869 में राष्ट्रीय महिला मताधिकार संघ और अमेरिकी महिला मताधिकार संघ बने। इन संघों का मुख्य उद्देश्य संविधान संसोधन द्वारा महिलाओं को मताधिकार उपलब्ध कराना था। ये दोनों संगठन 1890 में विलय हो गए तथा राष्ट्रीय अमेरिकी महिला मताधिकार संघ बना। इस संगठन के अनथक प्रयासों से 1920 में अमेरिकी महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष मताधिकार प्राप्त हुए।

भाग–II

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 5. राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-20, पृष्ठ 76,'राजनीतिक दलों के कार्य'

प्रश्न 6. आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) के किन्हीं दो रूपों पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-22, पृष्ठ 83,'आनुपातिक प्रतिनिधित्व'

www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

तुलनात्मक सरकार और राजनीति
(Comparative Government and Politics)

तुलनात्मक विधि और दृष्टिकोण

राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता

1

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

परिचय

तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की जाती है और यह कुछ नियमों और मानदंडों के आधार पर होता है। ऐसा नहीं है कि तुलना का कार्य केवल राजनीति में ही किया जाता है। यह कार्य अन्य विषयों, जैसे–समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में भी होता है। राजनीति में जिन तथ्यों की जाँच-पड़ताल होती है, वे समय के बदलाव के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। अत: यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि प्रचलित सिद्धांतों का प्रयोग देश, काल और परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए जैसे कि भूमंडलीकरण के दौर में नए-नए नियमों और नीतियों को अपनाने से पूर्व सावधानी बरती जानी चाहिए। वर्तमान में नए नियमों और सिद्धांतों की आवश्यकता है और इसके अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या नए सिरे से करनी होगी। इस अध्याय में राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और महत्त्व के बारे में बताया गया है।

अध्याय का विहंगावलोकन

राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन : प्रकृति और क्षेत्र

जैसा कि स्पष्ट है कि तुलना का कार्य केवल राजनीति विज्ञान में ही नहीं बल्कि अन्य विषयों में भी होता है, परंतु राजनीति में तुलना का कार्य एक अलग प्रविधि से होता है। तुलनात्मक राजनीति में तुलना के कई विषय होते हैं। जैसे कि सरकार के प्रकार, संविधान, राजनैतिक दल, सामाजिक आंदोलन आदि। तुलना का कार्य इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि आवश्यक प्रश्नों के उत्तर सरलता से प्राप्त हो सकें।

राजनीतिक में तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम राजनीतिक समस्याओं, व्यवहार और सरकारों का अध्ययन करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न देशों की सरकारों और राजनीति में व्याप्त समानताओं और असमानताओं का विश्लेषण करना है ताकि भविष्य के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके।

(1) तुलना : सम्बन्धों की पहचान–आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी एक देश की व्यवस्था और राजनीति की तुलना दूसरे देश से करना ही तुलनात्मक राजनैतिक अध्ययन है। दो देशों की समानता और असमानता के बारे में तुलना वास्तव में तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, जो कि सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से हो, तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। यह तुलना सीमित विषयों को लेकर नहीं होती, अपितु इसमें वे सभी विषय शामिल होते हैं जो कि राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें देश की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति तथा भौगोलिक दशा को शामिल किया जा सकता है। राजनीति को प्रभावित करने में इन

www.neerajbooks.com

सभी कारकों का योगदान होता है। सभी पहलू आपस में जुड़े होते हैं तथा तुलना में इनका समन्वित योगदान रहता है।

2. तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार–तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, तुलनात्मक सरकार में, सरकार संबंधी गतिविधियों पर चर्चा की जाती है जबकि तुलनात्मक राजनीति में सरकारी और गैर-सरकारी सभी गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का दायरा काफी विस्तृत है।

एक लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीति का केन्द्र पश्चिम के देश थे, परंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् नवस्वतंत्र और नवनिर्मित देशों को तुलनात्मक राजनीति में शामिल किया गया। तत्पश्चात् तुलनात्मक राजनीति को एक नई दिशा मिली। तुलना का कार्य एक नई परिस्थिति और नए परिवेश में प्रारंभ हुआ, यहीं से तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र और भी व्यापक हो गया। विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक दशा और वहाँ की संस्कृति का अध्ययन तुलना के लिए आवश्यक हो गया है।

इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् दो विरोधी विचारधाराओं का भी अभ्युदय हुआ जिसमें एक ओर पूंजीवादी देश तथा दूसरी ओर समाजवादी देश शामिल थे। इससे तुलनात्मक राजनीति को एक नया आयाम मिला, यहीं से तृतीय विश्व के देशों की भी उत्पत्ति हुई जो कि अधिकांशतः नवस्वतंत्र देश थे। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में इसको भी पर्याप्त स्थान दिया गया।

तुलनात्मक राजनीति : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

'राजनीति' का संपूर्ण इतिहास तुलनात्मक अध्ययन का इतिहास कहा जा सकता है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक दशा में परिवर्तन के कारण तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में परिवर्तन आता रहा है जिसके परिणामस्वरूप तुलनात्मक अध्ययन के विभिन्न पहलू भी बदलते रहे हैं।

1. राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत–अरस्तु और सिसरो के काल से ही राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत हो गई थी। बाद में मैक्यावली, कार्ल मार्क्स, लार्ड ब्राइस ने तुलनात्मक अध्ययन को विकसित किया।

यूनानी (विचारक) दार्शनिक अरस्तु ने 150 राज्यों के संविधानों का अध्ययन करके राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया। अरस्तु ने राजनीतिक व्यवस्था, जैसे–प्रजातंत्र, कुलीनतंत्र, राजतंत्र का विस्तृत वर्णन कर वर्गीकरण करके उन्हें अच्छे और बुरे दो भागों में बाँटा। पालीवियस ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया।

2. 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध–19वीं शताब्दी में लगभग 50 के दशक के बाद तुलनात्मक अध्ययन पर आदर्शवादी विचारों का प्रभुत्व रहा। इस काल में अध्ययन का केन्द्र यूरोपीय देशों (फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि) के आस-पास रहा। इसके अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को विश्व के अन्य देशों पर लादने का प्रयास किया गया। ऐसे में इसे पूर्णतः तुलनात्मक नहीं कहा जा सकता। नवस्वतंत्र विकासशील देशों को तुलनात्मक अध्ययन में शामिल नहीं किया गया। इसी काल में 1917 की रूसी क्रांति और प्रथम विश्वयुद्ध ने तुलनात्मक विचारकों को नए सिरे से सोचने पर विवश किया।

3. द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके बाद–द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व का दो अलग-अलग विरोधी विचारधाराओं में विभाजन हो गया। एक ओर (पश्चिमी) पूंजीवादी और दूसरी ओर (पूर्वी) साम्यवादी गुट था। इसके अतिरिक्त उपनिवेशिवाद के अंत के बाद, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्र-निर्माण, विकास आदि की अवधारणा, नवनिर्मित देशों के बीच, काफी लोकप्रिय हुई। ऐसे में अधिकांश देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया।

4. 1970 का दशक और विकासवाद की चुनौतियाँ–1970 के दशक में विकासवाद की आलोचना की गई जिसके अंतर्गत राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था में अंतर को समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत जातीयता पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसकी आलोचना की गई। अल्पविकसित देशों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने की बात कही गई। इस आलोचना में अमेरिका की विदेश नीति और बहुराष्ट्रीय नियमों की आलोचना भी शामिल है।

निर्भरता सिद्धान्त के समर्थकों का मानना यह भी है कि पश्चिमी देशों का विकास गैर पश्चिमी देशों के शोषण के परिणामस्वरूप हुआ है। मार्क्सवादी विचारकों का इस संदर्भ में कहना है कि शोषण का कारण समाज के एक वर्ग का राज्य पर नियंत्रण है, जिससे वह शेष भाग को अपने अधिकार व नियंत्रण में रखता है।

5. 1980 का दशक : राज्य की वापसी–1980 के दशक में विकासवाद में बिखराव आना शुरू हो गया। आलमंड ने 1950 में ही यह कहा था कि राज्य का स्थान राजनैतिक व्यवस्था को प्राप्त हो जाना चाहिए जिससे वैज्ञानिक आधार पर गतिविधियों को संचालित किया जा सके। ईस्टन ने भी राजनैतिक व्यवस्था में नए तत्त्वों का समावेश किया।

डॉनेल, रैल्फ मिलिबैंड, निकोस पोलैन्जा व पीटर इवेन्स ने राज्य को केन्द्र में रखकर नई विचारधारा की उत्पत्ति की। राज्य के बारे में नए ढंग से सोचा जाने लगा। विकासवाद के वर्चस्व को तोड़ा गया। इसके अलावा इसमें नए विकल्पों के बारे में ध्यान केन्द्रित किया गया।

6. 20वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध : भूमंडलीकरण और उभरती प्रवृत्तियाँ

(i) व्यवसायों का अध्ययन–1980 के दशक के पश्चात् तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विस्तृत हुआ। इसमें बड़ी मात्रा में विभिन्न देश शामिल हुए। इस काल में किसी खास उद्देश्य या मामले को गहराई से समझने पर जोर दिया गया। इसमें संस्कृति पर आधारित अध्ययन पर भी बल दिया गया। इसके साथ-साथ राष्ट्रीयता आधारित देश और संस्थागत विशिष्ट राष्ट्र पर विशेष बल दिया गया जैसे शासन व्यवस्था की किसी खास बात को लेकर भारत की किसी और देश से तुलना। तुलना का कार्य छोटे स्तर पर किया जाने लगा जैसे दक्षिण एशियाई देशों की आपस में तुलना।

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

***(ii)* नागरिक समाज और जनतांत्रिक दृष्टिकोण**–सोवियत संघ के पतन के बाद 'इतिहास का अंत' की अवधारणा सामने आई। इसमें उदारवादी प्रजातंत्र के वर्चस्व पर जोर दिया गया।

1980 में दशक के अंत में भूमंडलीकरण की अवधारणा उभरकर सामने आई। यह घटना पूरे विश्व को एक सूत्र में बाँधती है। देश की एक घटना का असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। सारी घटनाएँ पश्चिमी देशों के आसपास घटित हो रही हैं। इसके परिणामस्वरूप नागरिक समाज और जनतांत्रिक दृष्टिकोण का अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण में महत्त्व बढ़ रहा है और व्यक्तिगत अधिकारों की बात की जाने लगी है।

***(iii)* सूचना, संग्रहण और प्रसार**–भूमंडलीकरण में सूचना प्रोद्योगिकी, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइव वेब का तेजी से विकास हुआ है इससे आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण आसान हुआ है। इससे नए मुद्दे और विषय सामने आए हैं जो राष्ट्र-राज्य की प्रविधि को प्रभावित करते हैं। सामाजिक आंदोलनों में गति और प्रवाह जो सभी देशों को एकजुट करता है, इसका उदाहरण है।

राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता

राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता और महत्त्व से आशय इसकी प्रासंगिकता से है। तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक यथार्थ को समझने में हमारी मदद करता है। तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं की गहराई तक पहुँचने का सबसे अच्छा साधन है। इसकी उपयोगिता को निम्न तथ्यों से भली-भांति समझा जा सकता है–

1. सैद्धान्तिक निरूपण के लिए तुलना–तुलनात्मक अध्ययन में अध्ययन तुलनात्मक पद्धतियों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों को केन्द्र में रखकर विश्लेषण किया जाता है और सिद्धान्तों का निर्माण किया जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण निश्चित मानदंडों और नियमों के आधार पर किया जाता है। विश्लेषण के पश्चात् जो सामान्यीकरण आता है, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का निरीक्षण-परीक्षण किया जाता है। सामान्यीकरण जितना अधिक स्पष्ट होगा; निरीक्षण, परीक्षण उतना ही अधिक पारदर्शी और समझने योग्य होगा।

2. वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तुलना–यदि राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना जाए तो इसके लिए वैज्ञानिक विधियों का होना भी बहुत आवश्यक है। तुलनात्मक पद्धति में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, तत्पश्चात् निश्चित योजना के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अन्ततः आधारभूत सिद्धान्तों का निर्माण होता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित होता है।

3. संबंधों की व्याख्या के लिए तुलना–विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन के बिना हम किसी भी 'राजनीतिक संस्था' के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। एक लंबे समय से इसी परंपरा का पालन किया जाता रहा है। जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और गतिविधियों का उसकी समानता और असमानता के आधार पर परीक्षण किया जाता है विचारक संस्थाओं और गतिविधियों की समानता और असमानता के आधार पर तुलना को पर्याप्त नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन में औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सरकार के राजनीति के सभी तथ्य जो तुलना में शामिल हैं, के आपसी संबंधों को समझने में सहायता मिलती है।

4. प्रचलित सिद्धान्तों के आधार पर परीक्षण–तुलनात्मक राजनीतिक एक प्रयोगशाला की भाँति है जहाँ सिद्धांतों की जाँच-पड़ताल होती रहती है। इसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि अतीत में स्थापित सिद्धांत वर्तमान में प्रासंगिक हैं या नहीं। प्रचलित सिद्धांतों को परखने के लिए नए उपकरणों और नई विधियों का सहारा लिया जाता है। अंततः अनावश्यक और अप्रासंगिक सिद्धान्तों को त्याग दिया जाता है।

बोध-प्रश्न

प्रश्न 1. क्या यह कहना सही है कि तुलनात्मक राजनीति केवल सरकारों के अध्ययन की एक प्रविधि है?

उत्तर–तुलनात्मक राजनीति एक व्यापक अवधारणा है। यदि यह कहा जाए कि तुलनात्मक राजनीति केवल सरकारों के अध्ययन तक सीमित है, तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। रोनाल्ड शिलकोट ने इसके स्पष्टीकरण में बताया है कि तुलनात्मक सरकार का अध्ययन सरकारों के अध्ययन तक ही सीमित है जबकि तुलनात्मक राजनीति में सरकारी व अतिरिक्त गैर सरकारी सभी प्रकार की राजनैतिक बातों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार और राजनीति दो अलग-अलग शब्द हैं और इनका आशय भी भिन्न है। जब हम 'तुलनात्मक' सरकार की बात करते हैं तो हमारा आशय सरकार के प्रशासनिक अंगों, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों से होता है, परंतु इसमें राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रिया और गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन शामिल नहीं होता। दूसरी ओर तुलनात्मक राजनीति अपेक्षाकृत व्यापक अवधारणा है, इसमें राज्य से जुड़ी लगभग प्रत्येक गतिविधि का अध्ययन होता है। 'राजनीति' का संबंध केवल औपचारिक संस्थाओं (विधानमंडल, कार्यपालिका व न्यायपालिका) से ही नहीं, अपितु इसमें अनौपचारिक संस्थाओं (राजनीतिक दल, दबाव गुट) तथा गैर सरकारी समुदायों का अध्ययन शामिल है।

अंततः यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकार की ही चर्चा नहीं होती, इसके अंतर्गत गैर-सरकारी और अनौपचारिक संस्थाएँ भी शामिल की जाती हैं।

प्रश्न 2. ऐतिहासिक कालक्रम में बदलते सामाजिक-राजनैतिक सरोकारों के साथ-साथ तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और विस्तार में भी परिवर्तन आया। इस संबंध में अपना मत प्रकट कीजिए।

उत्तर–तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत अरस्तु से मानी जाती है। विभिन्न राज्यों के संविधानों का अध्ययन कर उसका वर्गीकरण किया। 15वीं शताब्दी में मैकियावेली ने विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था का अध्ययन कर तुलनात्मक राजनीति की परंपरा को आगे बढ़ाया।

www.neerajbooks.com

19वीं शताब्दी के पश्चात् यूरोप में उदारवाद का बोलबाला रहा और विचारकों का अध्ययन का केंद्र एक लंबे समय तक बना रहा। इसमें तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, शक्तियों का बंटवारा और सरकार के अंगों के आपसी संबंधों पर चर्चा होती रही।

20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में 1930 के पश्चात् दुनिया की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। 1917 की रूसी क्रांति ने विचारधारा और सिद्धांतों को गतिशीलता प्रदान की। सदी के प्रारंभ में विचारधारा और तुलनात्मक राजनीति के लिए नए नियमों और मानदण्डों के लिए दिशा मिली। द्वितीय विश्वयुद्ध ने इस क्षेत्र में एक नए ढंग से सोचने पर विवश किया। विश्व का दो गुटों में विभाजन और दो नई विचारधाराओं की उत्पत्ति तुलनात्मक राजनीति के लिए एक नया आयाम थी। 1960-70 के दशक के पश्चात् राजनीति में व्यवहारवादी आंदोलन को बल मिला और राजनीति की व्याख्या और परिष्कृत विधियों द्वारा की जाने लगी, जिसमें मूल्य निरपेक्षता और वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया गया।

इसके अतिरिक्त नए राष्ट्रों के उदय ने राजनीतिक विचारकों को आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में सोचने पर विवश किया। विकासशील देशों की समस्याओं ने एक नई विचारधारा को दिशा प्रदान की। इसी काल में कई राजनीतिक विचारकों ने नए-नए सिद्धान्तों का निर्माण कर तुलनात्मक राजनीति को गति दी। जैसे डेविड ईस्टन का व्याख्या उपागम, आमंड, कोल मैन पाई के राजनीतिक विकास के सिद्धांत आदि। 1960 के पश्चात् तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में काफी परिवर्तन आया। इसका क्षेत्र और भी व्यापक हुआ। इसमें पुरातन सिद्धान्तों का उपयोग नई परिस्थितियों में किया गया और राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन एक नए तरीके से किया गया। संस्थागत और संस्कृति के आधार पर राष्ट्रों का अध्ययन किया गया।

20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भूमंडलीकरण एक महत्त्वपूर्ण घटना है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने राजनीति के अध्ययन में एक नई दिशा प्रदान की है। इसमें आंकड़ों को आसानी से प्राप्त कर निरीक्षण-परीक्षण को अंतिम रूप दिया जाने लगा है।

प्रश्न 3. आपके अनुसार राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है?

उत्तर–राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता इस बात में है कि प्रचलित सिद्धांतों का प्रयोग राजनीति में हो रहा है और तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग भी हो रहा है। इसकी उपयोगिता इस बात में भी है कि इसमें केवल राजनीतिक संरचनाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में कितना प्रभाव रहा, का भी अध्ययन किया जाता है।

तुलनात्मक पद्धति न केवल राजनीतिक अपितु समाजिक परिवेश के अध्ययन पर भी जोर देती है। अतः तुलनात्मक विश्लेषण राजनीति की विभिन्नताओं का विश्लेषण करते हुए उसे व्यापक स्वरूप प्रदान करता है, इसलिए मेक्रेडिज तुलनात्मक पद्धति को वैज्ञानिक विश्लेषण के नाम से पुकारता है, क्योंकि इसमें निश्चित नियमों और सर्वमान्य सिद्धांतों द्वारा निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है, इस पद्धति में सूक्ष्म और गहराई से अध्ययन किया जाता है।

तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की लोकप्रियता के और भी कई कारण हैं। यह राजनीति के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्त्व रखता है। इससे वे केवल एक ही नहीं अपितु उसी प्रकार की कई भिन्न संरचनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तुलना द्वारा राजनीति के किसी भी पहलू पर विचार कर निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं। इससे तुलनात्मक राजनीति का गहराई से अध्ययन करने में मदद मिलती है।

अंत में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि नई विधियों और उपकरणों से विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं और तुलनात्मक कार्य को संपन्न किया जा रहा है। इससे निःसंदेह ही राजनीति के अध्ययन में लाभ पहुँचेगा।

प्रश्न 4. तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र को निर्धारित करने वाली क्या विशिष्टताएं हैं?

उत्तर–तुलनात्मक राजनीति में कई ऐसी बातें हैं जो इसको अन्य विषयों से अलग बनाती हैं। राजनीति में तुलना कई बातों और विषयों को लेकर होती है, जैसे–संविधान, राजनैतिक दल, सामाजिक-आर्थिक दशा आदि। अन्य विषयों में तुलना का कार्य इतना अधिक व्यापक और विस्तारपूर्वक नहीं होता जितना कि तुलनात्मक राजनीति में होता है। तुलनात्मक राजनीति के प्राचीन विचारकों ने तो सरकारी संरचनाओं–विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही को ही राजनीति का विषय-क्षेत्र मान लिया था, परंतु आजकल 'संस्थाओं' के बजाए 'कार्यपद्धति' और व्यवहार पक्ष पर जोर दिया जाने लगा है।

विशेष तौर पर द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् दो विरोधी विचारधारा की उत्पत्ति हुई और तृतीय विश्व के देशों को भी तुलनात्मक राजनीति में शामिल किया गया। तुलना के लिए नए-नए विषय उभरकर सामने आए। राजनीति को समझने के लिए नई विधियों और सूत्रों का प्रयोग किया गया। विकासशील देशों के समक्ष आधुनिकीकरण, राष्ट्रनिर्माण, नगरीकरण जैसे मुद्दे थे। गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना और एक अलग पहचान के लिए प्रयास करना राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव डालता है। 1980 के दशक में सोवियत संघ का पतन तथा विश्व का एकध्रुवीय होना तुलनात्मक राजनीति में गतिशीलता का समावेश करता है, इससे एक नई विचारधारा का व्यावहारिक पक्ष समाप्त हो गया। इसी काल में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिला और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में एक और अध्याय जुड़ गया। यह प्रक्रिया मुख्यतः अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यह राज्यों के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही है। इसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आया। तुलना के पैमाने में भी परिवर्तन आया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा पारिस्थितिक विज्ञान का समावेश होता जा रहा है। यही सब बातें तुलनात्मक राजनीति में प्रकृति और क्षेत्र में विशिष्टता प्रदान करती हैं।

Neeraj Publications www.neerajbooks.com